Nav Jyoti, Vol. 5, No. 11, July-December 2017 ISSN : 2249-7331

औपनिवेशिक भारत में ग्रामीण विकास : एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण (1900–1947)

डॉ0 मनोज कुमार तिवारी
असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग,
दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

भारत एक कृषि प्रधान, गांवों के देश के रूप में सुविख्यात है। भारतीय ग्रामीण जीवन का अनुशीलन, समस्याओं एवं प्रगति का विश्लेषण प्राचीन काल से ही कथाओं, कहानियों, लोकगीतों, उपन्यासों, जनश्रुतियों, धर्मग्रन्थों एवं कुछ आधुनिक शोध संस्थानों जिनमें–नेशनल इंस्टीच्यूट आफ रूरल डेवलपमेन्ट (हैदराबाद), सेन्ट्रल रिसर्च सेल एसोसिएशन आफ वालन्टरी एजेन्सी फॉर रूरल डेवलपमेन्ट इण्डियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीच्यूट, (नई दिल्ली), समन्वित ग्रामीण क्षेत्रीय विकास केन्द्र, बी0एच0यू0 (वाराणसी) इत्यादि प्रमुख है, के माध्यम से होता रहा है। परन्तु इसके बावजूद भी 'भारतीय ग्राम्य विकास के इतिहास' जैसे गूढ़ विषय पर बहुत कम लिखा गया है।

उदारीकरण, बाजारीकरण एवं वैश्वीकरण के वर्तमान युग में भी अविकसित तथा विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण विकास एक महत्वपूर्ण समस्या है। विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। भारत तो सदियों से आज तक गाँवों का देश कहा जाता रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले सस्ते श्रमिकों का सबसे बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। वर्तमान में विकास के नित नये प्रतिमानों की स्थापना के बावजूद, कोले[1] का मानना है कि, 'सदियों से ग्रामीण इलाकों में गरीबी है, जिसे जल्द समाप्त नहीं किया जा सकता, यद्यपि की विश्व के कई संगठनों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए समितियां बनायी गयी है, जो ग्रामीण जीवन की समस्याओं का अध्ययन कर उसके निराकरण का उपाय सुझा रही हैं।'

आधुनिक युग में ग्रामीण समस्याओं के व्यापक पैमाने पर सम्यक अध्ययन एवं उनके समाधान का सर्वप्रथम उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में दिखाई देता है। अमेरिका में ही सर्वप्रथम समन्वित क्षेत्रीय विकास की रूपरेखा प्रादेशिक नियोजन की प्रारम्भिक नीति के रूप में प्रस्तुत की गयी।[2] 1907 में अमेरिकी प्रेसिडेण्ट रूजवेल्ट ने ग्रामीण जीवन आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने कृषक, ग्रामीण जीवन ग्राम्य प्रतिनिधियों की स्थिति एवं उनकी समस्याओं का लाखों प्रश्नावलियों के माध्यम से अध्ययन कर 1911 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें आयोग ने स्वयं की नियुक्ति के औचित्य को स्पष्ट करते हुए लिखा कि–''आयोग की नियुक्ति इसलिए की गयी है कि अब समय आ गया है जबकि राष्ट्रहित के लिए कृषि जीवन की समस्याओं पर गम्भीरता से विचार किया जाय। कृषि जीवन की समस्याओं पर अब तक बहुत कम ध्यान दिया गया है, जिसका परिणाम उनके लिए अच्छा नही रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे है। इसलिए यह सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए अच्छा नही है।''[3]

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए सारगर्भित उपाय सुझाये। इस रिपोर्ट के प्रकाशन के पश्चात् विश्व के सभी प्रमुख देशों के प्रबुद्धजन इससे अत्यन्त प्रभावित हुए तथा उन्होंने ग्राम एवं ग्रामीण जीवन की महत्ता के बारे में गम्भीरता से सोचना प्रारम्भ किया। पराधीन भारत का प्रबुद्ध वर्ग भी भारतीय ग्रामीण जीवन की समस्याओं के समाधान एवं उसके विकास के बारे में सोचने लगा। 20वीं शदी के प्रारम्भ में पराधीन भारतीय ग्रामीण जीवन का स्तर अत्यन्त ही निम्न कोटि का था। पहले से चली आ रही समस्याओं ने अत्यन्त ही विकराल रूप धारण कर लिया कुछ प्रमुख समस्याएं थी गरीबी, दरिद्रता, बन्धुआ मजदूरी, अशिक्षा, बेरोजगारी, ऋण ग्रस्तता, जाति–पात, छुआ–छूत, अश्पृश्यता, नशाखोरी, गन्दगी, भिक्षावृत्ति, अकाल, अतिवृष्टि, संक्रामक रोग, अवैज्ञानिक पिछड़ी कृषि, इत्यादि।

ग्रामीण भारत के जीवन स्तर के तरफ ध्यान देने का काम वास्तविक अर्थों में पहली बार सहकारिता आन्दोलन के द्वारा प्रारम्भ किया गया। वैश्विक स्तर पर आधुनिक सहकारिता आन्दोलन का जन्म 19वीं शदी में यूरोप में हुआ, जिसके जनक के रूप में रॉबर्ट ओवन (1771–1858) को देखा जाता है। भारत में आधुनिक सहकारिता आन्दोलन का प्रारम्भ फ्रेडरिक निकोलसन के द्वारा किया गया उन्हें

आधुनिक भारतीय सहकारिता आन्दोलन का जनक माना जाता है। उनके सुझावों के आधार पर 1904 में सरकार द्वारा सहकारी समिति अधिनियम बनाया गया जिसका उद्देश्य किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। तत्पश्चात् 1912 में ''क्रय–विक्रय'' सहकारी समिति अधिनियम बनाया गया जिससे किसान लाभान्वित हुए और उनमें एक साथ काम करने की प्रवृत्ति धीरे–धीरे विकसित होने लगी। 1919 ई0 के माण्टेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा 'सहकारिता' को प्रान्तीय विषय घोषित करते हुए यह तय किया गया कि प्रत्येक प्रान्त अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सहकारी समितियों से सम्बन्धित नियम–कानून बनाये। सहकारिता आन्दोलन यद्यपि कि 20वीं शदी के प्रथमार्द्ध तक बहुत मजबूत एवं संगठित स्वरूप नहीं प्राप्त कर सका, परन्तु इसने ग्रामीण इलाकों में जागरूकता लाने, साथ–साथ काम करने की पुरानी प्रवृत्ति को पुनः विकसित करने तथा किसानों एवं गरीबों को कुछ मदद पहुचाने में सफल रहा तथा स्वतन्त्रता के पश्चात् 'सहकारिता ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का एक प्रमुख अंग बना।

रविन्द्र नाथ टैगोर[4] का भारतीय ग्रामीण जीवन से गहरा लगाव था। उन्होंने ग्रामीण जीवन के उन्नयन के लिए अथक प्रयत्न किया। उन्होंने बंगाल में 'श्री निकेतन सूरज ग्राम परियोजना' प्रारम्भ की। श्री निकेतन कलकत्ता से 14.4 किमी0 दूर, कृषि की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ, मलेरिया एवं हैजा जैसे संक्रामक रोगों से ग्रस्त एक गरीब गाँव था। इस गाँव को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए यह परियोजना प्रारम्भ की गयी। यहीं पर टैगोर ने 1914 ई0 में ''विश्वभारती की स्थापना की तथा 1921 में इसमें **'ग्रामीण पुनर्निमाण विभाग**' खोला गया। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम, ग्रामीण एवं ग्रामीण समस्याओं को समझने के लिए अनेक सर्वेक्षण किये गये। कृषि के विकास के लिए फलों एवं सब्जियों की कृषि को प्रोत्साहित किया गया। कुटीर उद्योगों में चर्म उद्योग, कुम्हारगिरी एवं बढ़ईगिरी को प्रोत्साहन दिया गया। पशुओं की नस्ल को उन्नत बनाने की कोशिश की गयी, सहकारिता हेतु प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया, स्वास्थ्य केन्द्र एवं सहकारी स्वास्थ्य समितियां बनायी गयी, ग्रामीणों को पढ़ना–लिखना एवं हिसाब लगाने के लिए प्रशिक्षित करने की कोशिश हुई, मनोरंजन हेतु नाटक एवं खेलकूद की व्यवस्था की गयी तथा बालचर संगठन बनाकर, उसका उपयोग ग्राम रक्षा हेतु किया गया। यह परियोजना कुछ समय तक आंशिक रूप से सफल रही परन्तु धनाभाव, अवैतनिक कार्यकर्त्ताओं, सरकार के असहयोग, समाज से अपेक्षित सहयोग के अभाव इत्यादि के कारण अन्ततः असफल हो गयी।

गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर श्री एफ0एल0 बायने[5] (1920–1926) ने गुड़गांव जिले की विभिन्न समस्याओं के समाधान के रूप में एक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसे गुड़गांव योजना के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र कम वर्षा, अनुपजाऊ भूमि, बीमारियों के प्रकोप तथा अधिकतर जंगल–झाड़ के लिए विख्यात था। जनता गरीबी, अज्ञानता, फिजूलखर्ची इत्यादि से ग्रस्त थी।

इस योजना के अन्तर्गत मुख्यतः सहकारिता, शिक्षा, कृषि एवं सामाजिक सुधार को स्वस्थ सामाजिक संगठन के निर्माण के साधन के रूप में प्रयोग करने की कोशिश की गयी।[6] कृषि उपज, पशुओं की नस्ल में सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा को प्रोत्साहन, मनुष्य, घर, गाँव की सफाई, फिजूलखर्ची, अन्धविश्वासों इत्यादि को समाप्त करने पर बल दिया गया। वैतनिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गयी, जिन्हें ग्राम गाइड कहा जाता था। इनका कार्य ग्रामीणों को हर संभव सहायता प्रदान करना, उन्हें सिखाना तथा प्रशिक्षित करना था। आज के समय में नियुक्त होने वाले ग्राम मित्र शायद उसी से प्रेरित है। पूरे जिले में लागू इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार एवं सफलता के लिए जादू, कार्टून, नाटक, गीत, ग्रामोफोन, प्रदर्शनी, पुस्तकों इत्यादि का प्रयोग किया गया। ब्रायने के कार्यकाल में यह योजना काफी सफल रही। उनके स्थानान्तरण के पश्चात जनता एवं कार्यकर्ताओं में उत्साह के अभाव, ग्राम गाइड की अनुभवहीनता, नये अधिकारियों की अरूचि इत्यादि के कारण यह योजना अन्ततः असफल हो गयी।

1928 ई0 में केरल के मारथेण्डम ग्राम के आस–पास के 5 किमी0 के अन्तर्गत स्थित 40 गांवों को लेकर स्पेन्सर हैच[7] ने वाई0एम0 सी0ए0 (यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन) के माध्यम से मारथेण्डम योजना प्रारम्भ की। इस योजना को इसाई चर्चों का सहयोग प्राप्त था। यह क्षेत्र काफी पिछड़ा था। स्पेन्सर हैच का मानना था कि किसी संस्था द्वारा संचालित ग्रामीण उत्थान के कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण जीवन के आध्यात्मिक, मानसिक, भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों का पूर्ण विकास करना होता है। इस योजना के अन्तर्गत–वैज्ञानिक कृषि, ग्रामीण उद्योग, सहकारिता, पंचायत आदि के विकास पर ध्यान दिया गया तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया गया। यह योजना बहुत सफल हुई।

इससे प्रेरणा प्राप्त कर बड़ौदा, हैदराबाद और कोचीन इत्यादि में भी ग्राम्य विकास की ऐसी ही योजनाएं प्रारम्भ की गयी। परन्तु डॉ0 स्पेन्सर हैच की मृत्यु के पश्चात वाई0एम0सी0ए0 के नेतृत्व को लेकर काफी विवाद प्रारम्भ हो गया। नेतृत्व के विवाद ने, अवैतनिक कार्यकर्ताओं के उत्साह पर प्रभाव डाला, अब वे उदासीन होने लगे। साथ ही व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम होने के नाते, सरकारी सहयोग के अभाव इत्यादि ने इस योजना को असफल बना दिया और अन्ततः यह समाप्त हो गयी।

इस समय तक गाँधी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर भारतीय राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो चुके थे। गाँधी ने देशाटन एवं पद यात्राओं के माध्यम से देश के नगरों के साथ–साथ ग्रामीण इलाकों का भी गहराई से अध्ययन किया। गाँधी भारतीय ग्राम्य जीवन की समस्याओं से काफी व्यथित थे। राष्ट्रीय आन्दोलन के इस दौर में उन्होंने आर्थिक समानता के सिद्धान्त पर बल देते हुए कहा कि 'अपनी स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। वे 'प्रत्येक को उनकी आवश्यकतानुसार', के मार्क्सवादी सिद्धान्त में विश्वास करते थे। उनके अनुसार आर्थिक समानता के मूल तत्व है–प्रत्येक परिवार को सन्तुलित भोजन, रहने के लिए मकान एवं शिक्षा की सुविधा। गाँधी ने तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए ग्रामोद्वार का वीणा उठाया।[8]

गाँधी ने ग्रामों के पुनर्निमाण के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लोगों में स्वदेशी की भावना जागृत करने के लिए, आर्थिक विषमता समाप्त करने के लिए, सामाजिक सद्भाव कायम रखने के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, ग्रामीणों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक गम्भीर कार्यक्रम चलाये जिनमें 18 सुत्रीय साबरमती कार्यक्रम (1920 ई0), सेवाग्राम[9] (1934) तथा अछूतोद्धार इत्यादि प्रमुख थी। गाँधी का मानना था कि स्कूल गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। उनकी बुनियादी शिक्षा का मूल मन्त्र 'हाथ से काम करके कमाने एवं सीखने का था।'

गाँधी ने ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम शुरू किये उसके अन्तर्गत चरखे का प्रयोग, सूत की कताई, खादी का प्रयोग, धान कूट कर चावल तैयार करना, गुड़ बनाना, नीम का तेल निकालना, हाथ से कपड़ा बुनना, मृत पशुओं का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग, हाथ से कागज बनाना, ऊनी कम्बल तैयार करना, प्रारम्भिक एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, ग्रामों की सफाई, दलितोद्धार, अस्पृश्यता के अन्त, नारी कल्याण का कार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं आरोग्य शास्त्र की शिक्षा, साम्प्रदायिक सौहार्द्र, नशाबन्दी, मात्र भाषा का प्रसार इत्यादि प्रमुख थे।

महात्मा गाँधी प्रायः कहा करते थे कि भारत की आत्मा उसके गाँवों में निवास करती है और भारत का उद्धार उसके गाँवों के पुनर्निमाण में निहित है। यदि देश का विकास चाहते हो तो 'गाँवों की तरफ चलो'।[10] गाँधी के ये कार्यक्रम और विचार स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत सरकार के ग्रामीण विकास से सम्बन्धित योजनाओं के प्रमुख आधार स्तम्भ बने। ग्राम्य विकास की गाँधीवादी अवधारणा के आधार पर ही देश में 2 अक्टूबर 1952 ई0 को 'सामूहिक विकास कार्यक्रम' प्रारम्भ किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य गाँवों के किसानों, मजदूरों, हस्तशिल्पियों एवं अन्य निर्धन वर्गो की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार करना था।

औपनिवेशिक भारत में ग्राम्य विकास के क्षेत्र में लगे लोगों में एक और प्रमुख नाम जो उभर कर सामने आया वो था वी0आई कृष्णामचारी का। इनके द्वारा बड़ौदा में कसम्बा ग्राम विकास परियोजना (1931–32) प्रारम्भ की गयी। इसका उद्देश्य ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार, ग्रामोद्योगों का विकास, ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण एवं सामाजिक विकास था। इसका अत्यन्त ही सकारात्मक असर आस–पास के इलाकों में दिखाई दिया। 1935 ई0 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत 1937 ई में सम्पन्न हुए चुनावों में कई प्रान्तों में कांग्रेस की सरकारें गठित हुई। इन कांग्रेसी सरकारों ने अपने–अपने राज्यों में ग्रामीण विकास कार्यक्रम उत्साह के साथ प्रारम्भ किया। इन कार्यक्रमों में–माडल ग्राम की स्थापना, गाँवों में हितकारी केन्द्रों की स्थापना, ग्राम–संचार की सुविधाओं का विकास, व्यापक स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को लागू करना, ग्रामोद्योगों का विकास एवं प्रान्तों में जिला बोर्डो की स्थापना इत्यादि के तरफ ध्यान दिया गया।

मद्रास राज्य में 1946–1947 ई0 में फिरका[11] विकास योजना प्रारम्भ की गयी। जिसका उद्देश्य था गाँधी के ग्राम्य विकास की अवधारणा के आधार पर ग्राम स्वराज्य को प्राप्त करना। इसके उद्देश्य थे–शिक्षा का विकास, ग्राम स्वच्छता, लोगों में आत्मविश्वास लाना एवं उनका आर्थिक विकास। इस योजना के अन्तर्गत जो प्रमुख कार्यक्रम अपनाये गये वो थे–ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के साधनों का

विकास करना, स्वच्छ जल की व्यवस्था करना, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण इलाकों में सहकारी समितियों का निर्माण, स्वच्छता, सिंचाई के साधनों का विकास, पशुधन का विकास, ग्रामीण उद्योगों का विकास इत्यादि। परन्तु यह आदर्श योजना केन्द्रीय सहयोग न मिलने के कारण तथा विभागीय असहयोग के कारण अधिक सफल न हो सकी।

इसी समय अर्थात् 1947 ई0 में डॉ0 विलियम एच0 फिशर के द्वारा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में 'भारतीय ग्राम सेवा' नामक योजना प्रारम्भ की गयी। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को शिक्षा के द्वारा स्वावलम्बी बनाना था। इसके लिए जनता की विकास कार्यो में भागीदारी एवं संगठनात्मक प्रयासों पर ध्यान दिया गया और ग्राम स्तरीय सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की नियुक्तियां की गयी तथा उद्देश की पूर्ति के लिए स्वास्थ्य, गृह विज्ञान, विकास, मनोरंजन, शिक्षा, कुटीर उद्योग, परिवार नियोजन आदि से सम्बन्धित कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये। यह योजना अपने क्षेत्रों में काफी हद तक सफल रही परन्तु ईसाईयों द्वारा चलाये जाने के कारण इसे उच्च वर्ग के लोगों का सहयोग कम मिला।[12]

बीसवीं शदी के प्रथमार्द्ध में भारत में ग्राम्य विकास से सम्बन्धित विचार एवं अवधारणायें अभी जन्म ले रही थीं। अभी ये शैशवावस्था में थीं। इन्होंने कोई निश्चित आकार नहीं ग्रहण किया था। परन्तु इसके बावजूद भी इन्होंने ग्रामीण विकास के बुनियादी तत्वों को तय कर दिया। इन्होंने एक दिशा तय की जिस पर काम शुरू हुआ। 20वीं शदी के प्रथमार्द्ध भी ग्राम्य कल्याण एवं विकास से सम्बन्धित अधिकांश योजनाएं निजी प्रयत्न का परिणाम थी। योजना प्रारम्भ करने वाले व्यक्तियों की बढ़ती लोकप्रियता ने विद्वेष एवं विरोध को जन्म दिया। साथ ही धनाभाव, औपनिवेशिक सरकार की उदासीनता एवं असहयोग, अवैतनिक स्वयंसेवकों की अरूचि एवं जागरूकता की कमी ने अधिकांश योजनाओं को सफल नहीं होने दिया। परन्तु इसके वावजूद सरकारी, गैर सरकारी व्यक्तियों, संस्थाओं के द्वारा प्रारम्भ की गयी योजनाओं ने, स्वतन्त्र भारत की सरकार को जो अनुभव एवं आधारभूत दृष्टिकोण प्रदान किया उसके फलस्वरूप विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा नियोजित ग्रामीण विकास के अनेक कार्यक्रम शुरू किये गये। साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अनेक जागरूक व्यक्तियों तथा समाज सुधारकों के द्वारा भारतीय ग्रामीण जीवन को प्रगतिशील और उन्नत बनाने की निरन्तर कोशिशें प्रारम्भ हुई।

सन्दर्भ

1. जॉन कोले, नीडेड ए रेडिकल अटैक आन रूरल पावर्टी, कुरूक्षेत्र, 1996, पृ0 10
2. जी0एल0 शाह, स्पेशियल ऑर्गनाइजेशन आफ रूरल सेटलमेन्ट इन द माउण्टेनियस पार्ट आफ यू0पी0 : ए स्टडी इन इन्टीग्रेटेड एरिया डेवलपमेन्ट, 'सिम्पोजियम आन ज्यॉग्राफरस् एण्ड रीजनल प्लानिंग (एब्सट्रैक्ट), 18–19 मई, 1979, यूनिवर्सिटी आफ गोरखपुर, पृ0 9.
3. तेजमल दक, भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, इलाहाबाद, पृ0 49–50.
4. जे0 सिंह, 'की इश्यूज : इन्टेग्रेटेड रूरल डेवलपमेन्ट', एफ0एस0एच0 डिवीजन, एफ0ए0ओ0, रोम, 1975, पृ0 1.
5. जे0 सिंह एण्ड आर0पी0मिश्रा, रिजनल डेवलपमेन्ट प्लानिंग इन इण्डिया, नई दिल्ली, 1978, पृ0 2.
6. शिवशंकर सिंह, भारत में समन्वित ग्रामीण विकास एवं नियोजन, नई दिल्ली, 1978, पृ0 X.
7. जे0एस0 माथुर, 'एरिया प्लानिंग–ए क्रिटिकल रिव्यू एण्ड रिजनल डेवलपमेन्ट', टेन्थ कोर्स आन आर0आर0डी0, सितम्बर–अक्टूबर (1977), एन0आई0सी0डी0, हैदराबाद (अनपब्लिश्ड् पेपर), पृ0 1.
8. डॉ0 वी0पी0 वर्मा, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, आगरा, 1989, पृ0 349.
9. पी0 राय एण्ड बी0 आर0 पाटिल, मैनुअल फार ब्लाक लेवल प्लानिंग, नई दिल्ली, 1977, पृ0 30.
10. शिवशंकर सिंह, पूर्वोद्धृत, पृ0 10.
11. एफ0 ए0 ओ0, 'पॉलिसिज एण्ड इन्स्टिट्यूशनस फार इन्टिग्रेटेड रूरल एरिया डेवलपमेन्ट, ज्वाइंट रिपोर्ट आन द एक्सपर्ट कंसलटेशनस, कोलम्बो एण्ड नैरोबी सेशनस, वाल्यूम–I, रोम, 1977, पृ0 2.
12. प्रमोद सिंह, भारत में ग्रामीण विकास का इतिहास, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1985, पृ0 2–4.